शुगर इंडस्ट्री की मांग, मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए

[जयश्री भोसले | पुणे]

मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने की मांग कर रही देश की शुगर इंडस्ट्री ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग दरों की भी मांग की है। इंडस्ट्री इन दोनों राज्यों की शुगर की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो का अंतर चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा के साथ मुलाकात के दौरान इंडस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के लिए शुगर के फ्लोर प्राइस को बढ़ाकर 33 रुपये प्रति किलो और महाराष्ट्र के लिए 31 रुपये प्रति किलो करने की मांग की। पिछले कुछ महीनों में शुगर के दाम में आई गिरावट और गन्ना उत्पादन वाले मुख्य इलाकों में बकाया राशि के भुगतान को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसी महीने शुगर का फ्लोर प्राइस 29 रुपये प्रति किलो तय किया था। मुख्य सचिव के साथ इस मीटिंग में नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एनएफसीएसएफ) और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के प्रतिनिधि शामिल थे। नृपेंद्र मिश्रा ने उन सभी जगहों पर डेलिगेशन भेजने का निर्देश दिया, जहां भारतीय शुगर का एक्सपोर्ट संभव है।

इस्मा के गौरव गोयल ने कहा, 'हमने सरकार से शुगर के मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाने का आग्रह किया है, जो अभी 29 रुपये प्रति किलो है।' एनएफसीएसएफ ने महाराष्ट्र के लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलो और उत्तर प्रदेश के लिए 33 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है। उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रीमियम शुगर का उत्पादन होता है। ऐसे में देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में इसकी मांग बढ़ सकती है। एक ही कीमत पर ग्राहक हमेशा प्रीमियम क्वॉलिटी वाली चीनी खरीदना पसंद करेगा।

केंद्र सरकार ने 2 करोड़ टन शुगर के एक्सपोर्ट की इजाजत दी है, लेकिन इंडस्ट्री अभी इसका ज्यादा निर्यात नहीं कर पाई है। इसकी वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत घरेलू बाजार से काफी कम है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में शुगर मिल्स को-ऑपरेटिव सेक्टर के तहत ऑपरेट की जा रही हैं। इनके शुगर स्टॉक लेंडिंग बैंकों के पास गिरवी रखे होते हैं। शुगर की मौजूदा एक्सपोर्ट की कीमत 1900 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मिलों ने इससे कहीं ज्यादा वैल्यूएशन पर इसे बैंकों के पास गिरवी पर रखा है। महाराष्ट्र की शुगर मिलों के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस वजह से बैंक मिलों को शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बैंक एक्सपोर्ट की कीमत और चीनी के वैल्यूएशन के अंतर की भुगतान की मांग कर रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने मिलों को लोन दिया था।

एनएफसीएसएफ के प्रेसिडेंट दिलीप वलसे पाटिल ने बताया, 'हमने केंद्र सरकार से 55 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोड्यूसर सब्सिडी की मांग की है, जिसे शुगर मिलों की जगह सीधे बैंकों को ट्रांसफर किया जाए। इस तरह से मिलों को गिरवी रखे शुगर के एक्सपोर्ट की इजाजत मिल जाएगी।'

राज्यों के मुताबिक तय हो कीमत

- **इंडस्ट्री ने** उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में शुगर की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो का अंतर रखने की भी मांग की
- **शुगर इंडस्ट्री** ने उत्तर प्रदेश के लिए शुगर के फ्लोर प्राइस को बढ़ाकर 33 रुपये प्रति किलो और महाराष्ट्र के लिए 31 रुपये प्रति किलो करने की मांग की
- **केंद्र सरकार** ने इसी महीने शुगर का फ्लोर प्राइस 29 रुपये प्रति किलो तय किया था

ET
26/6/18